

बांग्लादेश को अमीरा फूड्स 60,000 टन चावल निर्यात करेगी



भारत में निर्यात पर रोक के चलते ऑर्डर पूरा करने के लिए थाईलैंड से चावल जुटा सकती है कंपनी

प्रभा जगन्नाथन

नई दिल्ली

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट चावल कंपनी अमीरा फूड्स को बांग्लादेश से 60,000 टन उसना चावल की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। कंपनी की दुबई इकाई अमीरा फूड्स डीएमसीसी इसकी आपूर्ति करेगी। धान की सीधे कुटाई करने के बजाय उसे कुछ देर उबालने और सुखाने के बाद की गई कुटाई से इस तरह तरह का चावल तैयार होता है।

3 करोड़ डॉलर मूल्य के चावल की आपूर्ति दिसंबर में होगी। यह 30,000 टन के दो कन्साइमेंट के जरिए ढाका भेजा जाएगा। बाढ़ के चलते बांग्लादेश को जल्द से जल्द चावल की जरूरत है।

2007-2008 से ही गैर-सुगंधित चावल की किस्मों के निर्यात पर रोक जारी रहने से देश में 180 लाख टन से ज्यादा चावल का भंडार जमा हो गया है। भारत से चावल निर्यात पर रोक के चलते अमीरा बांग्लादेश को निर्यात किए जाने वाले चावल का अधिकांश हिस्सा थाईलैंड से जुटा सकती है। भारत की अन्य चावल कंपनियां भी बांग्लादेश की ओर से जारी चावल आयात के टेंडर में शामिल होंगी और वे भी थाईलैंड की राह पकड़ सकती हैं।

अमीरा फूड्स के ग्रुप एमडी करण ए चानना ने ईटी को बताया, 'हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण सौदा है। हमने सबसे कम कीमत रखी थी।' उन्होंने बताया कि अगर भारत में चावल निर्यात पर रोक नहीं रहती तो कीमतों में और कमी आती। बांग्लादेश की ओर से चावल आयात का टेंडर 10 अक्टूबर को पूरा हुआ। उसना चावल की आपूर्ति क्रमशः 492.60 और 482.65 डॉलर प्रति टन की दो दरों पर की जाएगी। हालांकि इससे

पहले 444 डॉलर प्रति टन पर बांग्लादेश ने चावल आयात का कॉन्ट्रैक्ट किया था। थाईलैंड के चावल की तुलना में भारतीय उसना चावल सस्ता रहा है और अगर देश से गैर-सुगंधित चावल के निर्यात पर रोक नहीं होती तो ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियों को इसका फायदा मिलता।

अमेरिका में चावल और मक्का उत्पादन में गिरावट की आशंका तथा चीन और बांग्लादेश जैसे चावल उत्पादक देशों में बाढ़ के कारण वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत के चावल कारोबारियों और निर्यातकों का मानना है

कि निर्यात पर दो साल से चली आ रही रोक हटाने का यह सबसे सही समय है। दिल्ली के एक चावल निर्यातक ने बताया, 'निर्यात से जुड़ी स्थितियों पर लगातार नजर रहनी जरूरी है और हो सकता है कि एकबार में निर्यात खोल देना ठीक न हो, लेकिन रोक हटाने से फायदा ही होगा, क्योंकि देश में भंडारण की भारी समस्या है। अगले माह से चावल की खरीद शुरू हो जाएगी।'

चावल का मार्केटिंग सीजन एक अक्टूबर से शुरू हो गया है। उद्योग जगत का मानना है कि स्टॉक भरे रहने के कारण अगले महीने से सरकार पर दबाव काफी बढ़ जाएगा। बासमती के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य 900 डॉलर

प्रति टन रखा गया है और इसी तर्ज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य होने से उच्च गुणवत्ता वाले चावल के नाम पर घटिया क्वालिटी का चावल भेजे जाने की आशंका घट सकती है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के प्रेसीडेंट विजय सेठिया ने कहा, 'सरकार को समय-समय पर खोज खबर लेनी होगी। नहीं तो घरेलू बाजार में चावल की आम किस्मों की कीमत पर असर पड़ेगा।'

निर्यात से रोक हटाने का वक्त

अमेरिका में उत्पादन घटने की आशंका और चीन-बांग्लादेश में बाढ़ के चलते वैश्विक बाजार में चावल के दाम बढ़ गए हैं, लिहाजा भारतीय निर्यात पर रोक हटाने का यह बिल्कुल सही समय है